पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-109/2017

भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124 साल/2012 जिला-सारण से उत्पन्न

==========

विजय राय पिता-जगन्नाथ राय, निवासी-मोहल्ला-गुदारी बाजार छावनी, थाना - भगवान बाजार, जिला-सारण, छपरा, बिहार ।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-50/2017

भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/ 2012 जिला-सारण से उत्पन्न

==========

1. उदय राय और अरूण राय पिता-जगरनाथ राय

2. खोआ राय उर्फ खोय राय, पिता- जगरनाथ राय, दोनों निवासी गाँव -गुडरी बाज़ार, छावनी, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण ।

... ... अपीलार्थियों

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-102/2017

भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/ 2012 जिला-सारण से उत्पन्न

==========

1. जय राम साह और अन्य पुत्र-स्वर्गीय भगवान साह

2. सिया राम साह पुत्र-स्वर्गीय भगवान साह दोनों निवासी मोहल्ला-गुदारी बाजार छावनी, थाना - भगवान बाजार, जिला-सारण छपरा, बिहार ।

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-110/2017

भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/ 2012 जिला-सारण से उत्पन्न

==========

हरे राम साह पिता- स्वर्गीय भगवान साह निवासी मोहल्ला-गुदारी बाजार छावनी, थाना - भगवान बाजार, जिला-सारण, छपरा, बिहार ।

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

के साथ

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-165/2017

भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/ 2012 जिला-सारण से उत्पन्न

==========

रुस्तम अंसारी पिता- मोहम्मद हदीश उर्फ हदीश मियां, निवासी मोहल्ला -शेख टोली, टाउन, छपरा, थाना - भगवान बाजार, जिला-सारण, छपरा

... ... अपीलार्थी

बनाम्

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-109/2017

अपीलार्थी की ओर से - श्री प्रशांत भूषण, अधिवक्ता
राज्य की ओर से - श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
सूचक की ओर से - श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
श्री रघुबीर चौधरी, अधिवक्ता

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-50/2017

अपीलार्थी की ओर से - श्री, अजय कुमार पांडे अधिवक्ता
सुश्री श्यामा रानी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से - श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
सूचक की ओर से - श्री बिनोद मुरारी मिश्रा, अधिवक्ता

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-102/2017 में

अपीलार्थी की ओर से - श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य की ओर से - श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
सूचक की ओर से - श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता
श्री रघुबीर चौधरी, अधिवक्ता

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-110/2017 में

अपीलार्थी की ओर से - श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य की ओर से - श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक
सूचक की ओर से - श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
श्री रघुबीर चौधरी, अधिवक्ता

आपराधिक अपील (डी बी) संख्या-165/2017 में

अपीलार्थी की ओर से - श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता

श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता

श्री कोशलेंद्र राय, अधिवक्ता

राज्य की ओर से - श्री सुजीत कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) - मृत्यु पूर्व बयान - घटना के दो घंटे बाद सूचक का फर्दबयान दर्ज किया गया - दस्तावेज में उपस्थित चिकित्सक का अनुमोदन नहीं था, जिससे सूचक के बयान देने के लिए उसकी मानसिक व शारीरिक फिटनेस की पुष्टि होती - जांच एजेंसी ने सूचक के जीवित रहने के 30 दिनों के दौरान मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया - अधिकांश गवाह परिवार के सदस्य या 10 किमी दूर रहने वाले करीबी रिश्तेदार थे, जिससे घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति की स्वाभाविकता पर सवाल उठे - गवाहों के बयान काफी देर से (घटना के चार महीने बाद तक) दर्ज किए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हो गई - स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-3 अपने बयान से पलट गया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया - चिकित्सकीय साक्ष्य से संकेत मिला कि चोटें एक ही हथियार से लगी थीं, जिससे अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन हुआ कि कई हमलावरों ने अलग-अलग चाकुओं का इस्तेमाल किया समूह हमले के बजाय दो व्यक्तियों के बीच - अभियोजन पक्ष द्वारा इन गवाहों की जांच नहीं की गई, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकले।

माना गया, - मृत्यु पूर्व बयान में आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव था और बिना पुष्टि के यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता था - देरी से दिए गए बयानों और संयोगवश गवाहों के रूप में उनकी स्थिति के कारण अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय नहीं थे - स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों को दबाने और मेडिकल रिकॉर्ड की कमी ने अभियोजन पक्ष की कहानी के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा किया। उच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और साक्ष्य मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, खासकर मृत्युदंड वाले मामलों में। अपीलकर्ताओं को बरी किए जाने से अभियोजन पक्ष की खामियों और साक्ष्य अंतराल से मुक्त, निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम- माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक 24-06-2024

सभी वर्तमान अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के तहत दायर की गई हैं, जिसमें भगवान बाजार पी.एस. से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 765/2012 (सीआईएस पंजीकरण संख्या 4356/2014) में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, छपरा द्वारा पारित दिनांक 16.11.2016 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 22.11.2016 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रकरण संख्या 124 वर्ष 2012, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है तथा उन्हें एक माह के साधारण कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत तीन वर्ष, भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के अंतर्गत दो वर्ष तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए 10,000/- रुपये प्रत्येक का जुर्माना तथा 25,000/- रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं को 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा जुर्माना अदा न करने पर अपीलकर्ताओं को प्रत्येक चूक के लिए छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है तथा सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार हैः

2.1 30.06.2012 को ,सूचक गुदारी बाजार (छावनी) से घर लौट रहा था और लगभग 12:30 बजे दोपहर में, *मोहल्ला*-गुदारी बाजार (छावनी) के सभी अभियुक्तगण ने

सूचक को घेर लिया और पचास हजार रुपये की फिरौती की मांग की और उसे अपने माता-पिता से फिरौती की राशि लाने के लिए कहा अन्यथा वे उसे मार देंगे। इस विवाद पर रुस्तम अंसारी, उदय राय, विजय राय और जय राम साह ने सूचक को पकड़ लिया और उसे सड़क पर घसीट लिया और उसे जान से मारने के इरादे से विजय राय और हरे राम साह नाम के अभियुक्तगण ने पेट, छाती और *पंजरी* पर चाकू से वार किया और जब सूचक नीचे गिर गया तो सिया राम साह ने उसकी गर्दन से सोने की चेन और उसकी जेब से 350/-रुपये ले लिए। *हल्ला* होने पर, *मोहल्ला* के लोग, माँ, चाचा, सूचक के नाना, शिवलाल चौधरी और मुन्ना सिंह वहाँ पहुँचे और एक टेंपो द्वारा सूचक को सदर अस्पताल, छपरा लाए, जहाँ डॉक्टर ने इलाज के बाद हालत को गंभीर पाया और उसे पी.एम.सी.एच., पटना रेफर कर दिया।

2.2. एफ. आई. आर. के दर्ज होने के बाद, अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान शुरू की और अनुसंधान के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपीलार्थी/आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध किया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या -765/2012 (सी. आई. एस. पंजीकरण संख्या- 4356/2014) के रूप में पंजीकृत किया गया।

3. आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या-109/2017 में, हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण, सूचक की ओर से विद्वान वकील श्री रघुबीर चौधरी की सहायता से श्री अरुण कुमार और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना है।

3.1. आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या- 50/2017 में, हमने उत्तरदाता की ओर से सुश्री श्यामा रानी, राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह और सूचक के लिए विद्वान वकील श्री विनोद मुरारी मिश्रा की सहायता से अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील श्री अजय कुमार पांडे को सुना।

3.2. आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या- 102/2017 में, हमने अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर, उत्तरदाता की ओर से श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, श्री अरुण कुमार, वकील राज्य के लिए श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक और सूचक के लिए श्री रघुबीर चौधरी, वकील को सुना।

3.3. आपराधिक अपील (डी.बी.) संख्या- 110/2017 में, हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर, उत्तरदाता की ओर से श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, वकील, श्री अरुण कुमार वकील, की सहायता से श्री सुजीत कुमार सिंह, वकील, राज्य के लिए श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक और सूचक के लिए श्री रघुबीर चौधरी, वकील को सुना।

3.4. आपराधिक अपील (डी.बी.) सं. -165/2017 में, हमने अपीलार्थी की ओर से श्री नवीन निकुंज, वकील और श्री कोशलेंद्र राय, वकील की सहायता से विद्वान वकील श्री नागेंद्र राय और उत्तरदाता की ओर सेश्री रघुबीर चौधरी, वकील, राज्य के लिए श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

4. संबंधित अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत अनुसंधान कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने घायल व्यक्ति द्वारा दिए गए *फर्दब्यान* पर भरोसा किया है, जो एफ. आई. आर. के पंजीकरण से एक महीने की अवधि के बाद मर गए। विद्वान वकील ने आगे यह प्रस्तुत किया कि गवाह या तो मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं या मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के परिचित हैं।यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी-3 ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

4.1. इस स्तर पर यह भी तर्क दिया जाता है कि अनुसंधान अधिकारी (अभियोजन साक्षी-10) ने स्वतंत्र गवाहों अर्थात लालबाबू, ज्ञान प्रकाश, ललन साह, सोनामती देवी और छोटे लाल मांझी के बयान दर्ज किए थे। हालाँकि, उपरोक्त व्यक्तियों को आरोप पत्र में गवाह के रूप में उद्धत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने उक्त व्यक्तियों का परीक्षण नहीं की और इस तरह भौतिक तथ्य को दबा दिया। यह तर्क दिया जाता है कि अनुसंधान अधिकारी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उपरोक्त व्यक्तियों में से कुछ, जिनके बयान दर्ज किए गए थे, ने केवल एक आरोपी का नाम दिया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि कुछ व्यक्ति विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह थे, लेकिन अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उनकी परीक्षा नहीं की गई है और इसलिए, प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

5. इस स्तर पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचक का *फरदबयान* सहायक अवर निरीक्षक के द्वारा दर्ज किया गया था, और उक्त *फरदबयान* पर सूचक के बाएं अंगूठे का

निशान लिया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सूचक की स्थिति गंभीर थी और इसलिए, उसके अंगूठे का निशान लिया गया था। हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि घायल सूचक की परीक्षण करने वाले अभियोजन साक्षी-4, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, दाहिने हाथ में कोई चोट नहीं थी और इसलिए, पुलिस अधिकारी, जिन्होंने *फरदबयान* दर्ज किया था, घायल सूचक के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते थे। इस स्तर पर, यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घायल की हालत गंभीर थी, फिर भी उसका *फरदबयान* कैसे दर्ज किया गया, यह ज्ञात नहीं है।

6. तत्पश्चात विद्वान वकील ने तर्क दिया कि घायल के *फरदबयान* को दर्ज करते समय, जिसे उसकी मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया था, घायल का इलाज करने वाले डॉक्टर का समर्थन प्राप्त नहीं किया गया था। इसलिए, अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सूचक पुलिस के समक्ष अपना बयान देने की स्थिति में था या नहीं। इस स्तर पर यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यह घटना 30 जून, 2012 को हुई थी और घायल सूचक की एक महीने की अवधि के बाद यानी 30 जुलाई, 2012 को मृत्यु हो गई थी। उक्त अवधि के दौरान, घायलों को किस प्रकार का उपचार दिया गया था, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य के माध्यम से इंगित नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल सूचक तीस दिनों की अवधि तक जीवित रहा, जिसके बावजूद अनुसंधान एजेंसी ने घायल सूचक की मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया।

7. तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृतक के पिता पी.डब्लू.-8 का बयान घटना की अगली तिथि अर्थात् 01.07.2012 को दर्ज किया गया था। तथापि, अन्य गवाहों के बयान, जिन्होंने दावा किया है कि वे घटना के तुरन्त बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे तथा जिनके समक्ष घायल (मृतक) ने पूरी घटना बताई थी, अक्टूबर, 2012 में कहीं दर्ज किए गए थे। अन्यथा भी, मृतक के निकट संबंधियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान को भी खारिज किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उनमें बड़े विरोधाभास तथा विसंगतियां हैं। विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह इंगित किया गया है कि पी.डब्लू.-1 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो उसने सूचनाकर्ता को घायल अवस्था में पाया तथा जब उससे पूछताछ की गई, तो घायल ने घटना के बारे में बताया। इसी प्रकार, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-5, पी.डब्लू.-6 तथा पी.डब्लू.-7 ने भी यह बयान दिया है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो सूचना देने वाले ने

घटना का विवरण दिया। यह तर्क दिया गया है कि उक्त कहानी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घायल ने प्रत्येक गवाह के समक्ष पूरी कहानी सुनाई। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि जब सभी गवाह घटनास्थल पर पहुंचे तो घायल ने सभी गवाहों के समक्ष पूरी घटना का विवरण दिया। इस स्तर पर यह भी बताया गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त सभी गवाह 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे, इसलिए घटना के समय तथा स्थान पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी। इस प्रकार, उक्त गवाह संयोगवश गवाह हैं। इसलिए, उनके बयान को खारिज किया जाना आवश्यक है।

8. विद्वान वकीलों ने आगे कहा कि, घायल सूचक के मामले के अनुसार, घटना 12:30 बजे हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन साक्षी-4 के अनुसार, डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह, जिन्होंने 12:40 बजे घायलों की जांच की थी यानी घटना होने के समय से 10 मिनट के भीतर और उसके बाद उन्हें पी.एम.सी.एच पटना भेजा गया, इसलिए, 2:30 पर *फरदबयान* दर्ज छपरा अस्पताल में की गई जो कि संदेह पैदा करता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन साक्षी-4 ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि चोटों की प्रकृति से पता चलता है कि केवल एक हथियार का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, सूचक और अभियोजन पक्ष के गवाहों का यह सिद्धांत कि नामित अभियुक्त द्वारा अलग-अलग हथियारों से हमला किया गया था, संदेह पैदा करता है।

9. इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि यद्यपि दोषसिद्धि केवल मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करने पर दर्ज की जा सकती है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरी कहानी संदिग्ध है और सूचक द्वारा दी गई तथाकथित मृत्यु घोषणा संदिग्ध है, तो अपीलार्थियों की दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय एक त्रुटि की है। इसलिए विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि विवादित निर्णय और आदेश को रद्द और कर दिया जाए।

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों ने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः-

(i) **दर्शना देवी बनाम पंजाब राज्य, 1995** में रिपोर्ट किया गया पूरक **(4) एस. सी. सी. 126।**

(ii) **रमाकांत मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 8 एस. सी. सी. 126** में सूचित किया गया।

(iii) **शंकर चौधरी बनाम बिहार राज्य, 2023** में **एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 6764** में रिपोर्ट किया गया।

(iv) **पंजाब राज्य बनाम किक्कर सिंह, 2002** में **एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 543** में रिपोर्ट किया गया।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इन सभी अपीलों का विरोध किया है। यह तर्क दिया जाता है कि एक बार जब घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं एक मृत्यु घोषणा दी जाती है जिसमें उसने सभी अभियुक्तों के नाम बताए हैं और विशिष्ट भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया है, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। भले ही डॉक्टर का यह समर्थन न हो कि रोगी होश में था और अपना बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था, मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विशेष रूप से कहा है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे, तो घायल ने खुद पूरी घटना सुनाई और प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर इशारा किया। इस प्रकार, सूचक द्वारा मृत्यु घोषणा भी दी गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह भी तर्क दिया कि केवल इसलिए कि गवाह करीबी रिश्तेदार है उनके बयान को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन साक्षी-8 ने *फरदबयान* पर हस्ताक्षर किए हैं और जांच रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं।घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध करने का उद्देश्य भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विवादित आदेश पारित करते समय निचली अदालत द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः वर्तमान अपीलों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. सूचक के विद्वान अधिवक्तओं ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः-

(i) **बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 12 एस. सी. सी. 73** में रिपोर्ट किया गया।

(ii) **पंजाब राज्य बनाम संजीव कुमार और अन्य ने ए. आई. आर. 2007 एस. सी. सी. 2430** में रिपोर्ट किया।

(iii) **सुंदर सिंह बनाम उत्तरांचल राज्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 611** में रिपोर्ट किया गया।

(iv) **लखन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 514** में रिपोर्ट किया गया।

(v) **तेजराम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2015 (2) बी. एल. जे.** में सूचित।

13. इससे यह पता चलता है कि अभियोजन साक्षी-1 मदन मोहन नट ने बयान दिया है कि घटना के दिन वह मासूमगंज से गुडरी बाजार आ रहा था। उन्होंने वहाँ भीड़ को इकट्ठा होते देखा। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके पोते हर्ष रंजन राज उर्फ राजा घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हआ है। उसके पेट, छाती और पसलियों में चाकू के घाव दिखाई दे रहे थे और उन घावों से खून बह रहा था। जब उसने उससे पूछा तो उसने उसे बताया कि विजय राय, हरे राम साह, खोवा राय, उदय राय, जय राम साह, सियाराम साह और रुस्तम अंसारी ने उसे घेर लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर हरे राम साह और विजय राय ने उस पर चाकू से वार किया और फिर जय राम साह उसकी जेब से 350/- रुपये और एक सोने की चेन ले गए। वहाँ से वह उसे टेंपो पर लेकर सदर अस्पताल ले आया और आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद, डॉक्टरों ने घाव को देखकर उन्हें पी.एम.सी.एच पटना भेज दिया। घायल ने यह भी बताया था कि एक महीने पहले सभी आरोपी 50,000/- रुपये की फिरौती की मांग कर रहे थे और आज तक फिरौती की राशि नहीं दी इस कारण उन्होंने उसे घेरकर वार किया। इसके बाद घायल को पटना ले जाया गया जहां 30.07.2012 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

13.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि मृतक के पिता छपरा अदालत में वकील हैं।उसका पोता अपने माता-पिता के साथ रहता था। जब वह पहली बार घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दामाद हरीश कुमार, राम किशोर मिश्रा, राजीव नट, मुन्ना नट और शिवलाल चौधरी वहां खड़े थे।इन लोगों का घर गुडरी बाजार में नहीं है। ये लोग रामकृष्ण पुरी के निवासी भी नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि घटना स्थल पर कई लोग थे। वह उन्हें नहीं पहचानता। वह दुकानदारों के नाम भी नहीं जानता। इसके अलावा, उन्होंने

यह भी कहा है कि सड़क पर खून था।उन्होंने घायल (मृतक) को घटना स्थल से उठाया। जब वह उसे उठा रहा था, उसके कपड़ों और हरीश और मुन्ना के कपड़ों पर खून के धब्बे थे।खून से सना कपड़ा इंस्पेक्टर को नहीं दिया गया क्योंकि उसने इसकी मांग नहीं की थी। खून से सना कपड़ा इंस्पेक्टर को नहीं दिखाया गया क्योंकि वह उसके सामने नहीं आया था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पोते के खिलाफ फिरौती का कोई मामला था या नहीं। बाद में, उन्होंने कहा कि उनके पोते को रिविलगंज में दफनाया गया था। उक्त कब्रिस्तान मासूमगंज से कुछ दूरी पर है।

14. अभियोजन साक्षी-2 राज कुमार मिश्रा ने कहा है कि यह घटना 30.06.2012 को लगभग 12:30 बजे दिन में हुई थी। **उस दिन** गानिया कोठी से सामान लेकर वापस अपना घर छपरा लौट रहा था जब वह गुड़री बाजार पहुँचा तो उन्होंने भीड़ देखी। जब वह वहाँ गया तो उसने देखा कि हर्ष राज को चाकू मार दिया गया था। उन्होंने अपनी पसलियों, पेट, छाती और बाएं हाथ पर चाकू के घाव देखे। वहाँ, उसने हर्ष राज (घायल) को यह कहते हुए सुना कि आरोपी 50,000/- रुपये की फिरौती मांग रहे थे और यह घटना फिरौती की राशि का भुगतान न करने के कारण हुई और इस वजह से विजय राय और हरे राम ने उसे चाकू मार दिया।

14.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा है कि घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था। पुलिस उसके गांव आई और उसका बयान लिया।पुलिस के सामने, उसने कहा है कि हर्ष राज ने उसे बताया था कि 50,000/- रुपये की फिरौती की मांग की गई और जब यह नहीं दिया गया, तो उक्त घटना हुई। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि वह अपने नाना के माध्यम से मृतक से परिचित है।

15. अभियोजन साक्षी-3 शिवलाल चौधरी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं और मुकर गए हैं।

16. अभियोजन साक्षी-4 डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह सदर अस्पताल, छपरा में 30.06.2012 को एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। उसी दिन, लगभग 12:40 बजे अपराह्न, उन्होंने घायल सूचक के शरीर की जांच की और निम्नलिखित चोटें पायाः

"(i) बाएं हाथ पर तेज कट 2"x 1/2" x मांसपेशियाँ गहराई में,

(ii) पेट के बाईं ओर 2'x 1/2' x मांसपेशियों को गहरा काटना,

(iii) छाती के बीच के निचले हिस्से में 1/2"x 1/2" x मांसपेशियों की

गहराई में तेज कटौती,

(iv) बाएं अक्षतंतु के नीचे 1/2"x 1/2" x मांसपेशियों को गहराई से काटें।

(v) श्रोणि 1/2"x 1/2" गुहा के नीचे बाएं अक्षतंतु पर तेज कट।

समय-परीक्षा छह घंटे के भीतर।

प्रकृति-चोट सं-I से IV प्रकृति में सरल हैं जो चोट संख्या के लिए तेज काटने वाले पदार्थ के कारण होते हैं। (v) घायल को पी.एम.सी.एच पटना भेजा गया था, पी.एम.सी.एच द्वारा दी गई राय जारी की गई थी।

16.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस की मांग पर घायलों की जांच की और चोट की प्रकृति से पता चला कि केवल एक हथियार का उपयोग किया गया था।

17. अभियोजन साक्षी-5 मुन्ना नट ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना के समय वह गुडरी बाजार में था। यह घटना गुडरी बाजार छावनी में हो रही थी। जब वह वहाँ गया तो उसने देखा कि उसका भतीजा (मृतक) संघर्ष कर रहा था। उसे चाकू का घाव था। जब उसने उससे पूछा, तो उसके भतीजे ने उसे बताया कि विजय राय, उदय राय, खोवा राय, हरे राम साह, सिया राम साह 50,000/- रुपये की फिरौती मांग रहे थे और यदि उक्त राशि समय पर नहीं दी गई, तो आरोपी व्यक्ति उसके परिवार को छपरा में नहीं रहने देंगे और उसे जान से मारने की धमकी देंगे। **इस वजह से,** रुस्तम अंसारी, विजय राय, हरे राम राय और सिया राम साह ने उसे पीटा और उसके पेट, छाती, पसलियों और दाहिने हाथ में चाकू मार दिया।उसके बाद सिया राम ने अपने भतीजे की गर्दन से सोने की चेन छीन ली और उसकी जेब से 350/-रुपये ले गया। उसके बाद, उन्होंने घायल को उठाया और उसे सदर अस्पताल, छपरा ले गया। वहाँ से, डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए पी.एम.सी.एच पटना भेजा, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

17.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने इस मामले के सूचक के बारे में अज्ञानता दिखाई है। उसने कहा है कि घटना से पहले उसे फिरौती और धमकियों का मुद्दा बताया गया

था। पुलिस स्टेशन में उनका *सनहा* नहीं दिया गया था। फिरौती, माँग या धमकी के संबंध में किसी भी पुलिस स्टेशन को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा है कि यह घटना गुडरी छावनी में हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा था कि उनके घायल भतीजे ने उन्हें जो कुछ भी बताया था, वह सभी दुकानदारों के सामने बताया गया था।

18. अभियोजन साक्षी-6 उषा देवी घायल सूचक की माँ है जिसने अपने मुख्य परीक्षा में गवाही दी है कि उसके बेटे के चाकू से घायल होने की सूचना मिलने के बाद, वह गुडरी बाजार छावनी गई और देखा कि उसका बेटा सड़क पर पड़ा हुआ है। पूछने पर, उसके बेटे ने उसे बताया कि जब वह गुडरी बाजार से लौट रहा था, तो विजय राय, उदय राय, खोवा राय, हरे राम साह, जय राम साह, सिया राम साह और रुस्तम अंसारी उसे घेर लिया और उसे जातिवादी गालियों से गाली दी कि वे पिछले एक महीने से उसकी माँ से फिरौती की मांग कर रहे थे और उन्हें फिरौती के पैसे क्यों नहीं मिल रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिली तो वे उसके माता-पिता को छपरा में नहीं रहने देंगे और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, उसके बेटे ने उसे बताया कि आरोपी व्यक्तियों ने उसे मारने के इरादे से सड़क पर गिरा दिया। विजय राय और हरे राम साह ने उसके पेट, छाती, पसलियों और बाएं हाथ पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया जिससे वह घायल हो गया और सड़क पर गिर गया। उसने यह भी कहा है कि सिया राम साह ने उसके बेटे की गर्दन से सोने की चेन और उसकी जेब से 350/- रुपये छीन लिए। उनके बेटे का इलाज सदर अस्पताल, छपरा में किया गया। डॉक्टरों ने उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें पी.एम.सी.एच पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

18.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि वह घटना के दिन काम पर थी। उनका कार्यालय का समय 10:00 बजे सुबह से 04:00 बजे शाम तक है। उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके कार्यालय में कोई रजिस्टर नहीं था। वह दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकती कि घटना के दिन कोई कार्यालय नहीं था। उसने आगे कहा है कि उसके बेटे ने उसे पहले सूचित किया था कि फिरौती के पैसे की मांग की जा रही थी। वह इस बारे में सूचित करना चाहती थी, लेकिन इस बीच उक्त घटना हो गई । उसने आगे कहा है कि उसके कपड़ों पर खून का कोई दाग नहीं था, लेकिन उसके पति के कपड़ों पर खून के दाग थे, लेकिन वह कपड़ा पुलिस को नहीं दिया गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि घटना से पहले उसका बेटा रुस्तम अंसारी के साथ रहता था। जब तक वह घटना स्थल पर थी, कोई पुलिस अधिकारी वहां नहीं आया। पुलिस अस्पताल पहुंची

और घटना की जानकारी ली। उसका पति उसके बेटे को पी.एम.सी.एच पटना ले गया जहाँ उसका ऑपरेशन किया गया। उनके बेटे का *पोस्टमार्टम* पटना में किया गया, जिसके बाद उसे छपरा लाया गया। बाद में, उसने कहा कि उसका बयान पुलिस ने दस दिनों के बाद उसके घर पर दर्ज किया था। उसका घर घटना स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वह यह नहीं बता सकती कि घटना स्थल के पास कोई कब्रिस्तान है या नहीं। उन्होंने अपने बेटे को रिविलगंज में दफनाया क्योंकि उनकी जाति में दफनाने की प्रथा है।

19. अभियोजन साक्षी-7 राजीव कुमार नट ने कहा है कि जब उसने पहली बार घायल को देखा तो वह घायल हालत में लेटा हुआ था। उसकी छाती, पेट और बाईं पसली के पिंजरे पर चाकू से वार किया गया था। पूछने पर उसने कहा कि 50,000/- रुपये की फिरौती अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उससे मांग की जा रही थी, जिन्होंने उसे घेर लिया और उसे जातिवादी गालियों से गाली दी और फिर विजय राय, हरे राम साह ने उसके पेट और छाती में चाकू से वार कर दिया। **इसके बाद घायल को सदर अस्पताल,** छपरा जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें पी.एम.सी.एच पटना भेजा जहाँ 30.07.2012 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

19.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि वह उन लोगों में से थे जो घायलों को ले जा रहे थे। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। खून से सने कपड़े पुलिस को नहीं सौंपे गए। उन्होंने किसी भी कागज पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए।

20. अभियोजन साक्षी-8 हरीश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि वह मृतक के पिता है। उक्त घटना 30.06.2012 पर 12:30 बजे दोपहर में हुई। वह कोर्ट से टेंपो में अपने घर जा रहा था। गुदड़ी बाजार में हंगामा हो रहा था। हंगामा सुनकर वह वहाँ गया और देखा कि उसका बेटा वहाँ सड़क पर घायल हालत में पड़ा हुआ है। पूछने पर, उसके बेटे ने उसे बताया कि रुस्तम अंसारी, उदय राय, खोवा राय, विजय राय, जयराम, सिया राम, हरे राम साह पिछले एक महीने से 50,000/-रुपये की फिरौती मांग रहे थे। वे उन्हें जातिवादी गालियों से गाली दे रहे थे।फिर उन्होंने उसे सड़क पर पटक दिया और फिर विजय राय, हरे राम साह ने उसे मारने के इरादे से उसके पेट, छाती, पसली के पिंजरे, बांह के बाईं ओर बार-बार चाकू मारा। वहां से वह उन्हें इलाज के लिए टेंपो में सदर अस्पताल, छपरा ले गए। जब उनका सदर अस्पताल, छपरा में इलाज चल रहा था, तब पुलिस निरीक्षक आए और उनका बयान लिया, जिस पर उनके बेटे ने हस्ताक्षर किए थे और इसे प्रदर्श-1 के रूप में

चिह्नित किया था। चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसके बेटे को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। उनके बेटे का इलाज पी.एम.सी.एच पटना में किया जा रहा था। उपचार के दौरान, उनकी मृत्यु पी.एम.सी.एच पटना में 30.07.2012 को हुई।

20.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि घटना से पहले, वह इस बात से अनजान था कि आरोपी व्यक्ति उसके बेटे से फिरौती की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके बेटे का बयान पी.एम.सी.एच में लिया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि सदर अस्पताल, छपरा में इलाज कराने में दस मिनट की देरी हुई थी। पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। वह लगभग 02:30 बजे पी.एम.सी.एच पटना के लिए अस्पताल से निकले जहाँ उनके बेटे की मृत्यु 30.07.2012 को हुई। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे की रुस्तम अंसारी के साथ दोस्ती थी।

21. अभियोजन साक्षी-9 अरुण कुमार शर्मा अनुसंधान अधिकारी हैं जिन्हें भगवान बाजार पुलिस स्टेशन में 30.06.2012 को ए.एस.आई. के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें चोटों की रिपोर्ट मिली। छपरा के सदर अस्पताल पहुंचने के बाद घायल का बयान दर्ज किया गया जिस पर घायल ने खुद हस्ताक्षर किए थे।

21.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि एफ. आई. आर. लिखने से पहले उन्होंने घायल की स्थिति के संबंध में डॉक्टर से प्रमाण पत्र नहीं लिया था। *फरदबयान* पर डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे।

22. अभियोजन साक्षी-10 कुमार संतोष रजक भगवान बाजार पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। सूचना देने वाले के *फरदबयान* के आधार पर, भगवान बाजार कांड संख्या-124/12 की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। जब वह घायलों का बयान लेने अस्पताल गए तो उन्हें पता चला कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना भेज दिया गया है। अनुसंधान के दौरान उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। सूचक के गवाहों के बयान और चोट की रिपोर्ट के आधार पर रुस्तम अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और अन्य लोगों के लिए अनुसंधान जारी रखी गई। पूरक अनुसंधान के दौरान उन्हें मृतक की *पोस्टमॉर्टम* रिपोर्ट और चोट पत्र प्राप्त हुआ। 10.11.2012 को उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अनुसंधान की जिम्मेदारी एस. एच. ओ. को सौंप दी।

22.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि वह 01.07.2012 को पी.एम.सी.एच पटना गया था और घायल और उसके पिता का बयान लिया था। उसने रुस्तम अंसारी को गिरफ्तार किया था जिसने कहा था कि यह वही था जिसने चाकू मारा था।

23. अभियोजन साक्षी-11 राजेश्वर प्रसाद भगवान बाजार पुलिस स्टेशन में एस. आई. के रूप में 16.11.2012 को तैनात थे। एस. एच. ओ. द्वारा उन्हें भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/12 की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अदालत में आरोपी विजय राय के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके प्रस्तुत किया।

24. अभियोजन साक्षी -12 जोगेंद्र राम पी.एम.सी.एच पटना के मुर्दाघर में पोस्टमॉर्टम अटेंडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि डॉ. अनिल कुमार की मृत्यु हो गई है और *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट उनकी लिखावट में है जिसे उन्होंने पहचान लिया है और प्रदर्श-7 के रूप में चिह्नित किया है।

25. हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है। रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से मृतक द्वारा दिए गए *फरदबयान* पर भरोसा किया है और इसे मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया था। विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ-साथ सूचक के विद्वान वकीलों ने यह तर्क देते हुए उक्त साक्ष्य पर भरोसा किया है कि चूंकि घायल ने खुद घटना के तुरंत बाद पुलिस के समक्ष मृत्यु की घोषणा की है, उसी आरोपी के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है और किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह सच है कि यदि मृतक द्वारा दी गई मृत्यु घोषणा सही और विश्वसनीय पाई जाती है, तो बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। इसलिए, वर्तमान मामले में, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि केवल घायलों द्वारा दिए गए *फरदबयान* के आधार पर, अभियुक्तों को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है या नहीं।

26. रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि, फरदबयान के अनुसार, घटना 12:30 बजे हुई थी और *फरदबयान* दोपहर 2:30 बजे सदर अस्पताल, छपरा में दर्ज किया गया था। उक्त *फरदबयान* पर घायल सूचक के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन उसके बाएं अंगूठे का निशान पुलिस अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि सूचक *फरदबयान* पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था। इसके कारण उसके अंगूठे का निशान प्राप्त किया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि घायल की तुरंत 12:40 बजे

डॉक्टर द्वारा जाँच की गई थी और डॉक्टर ने घायल सूचक के बाएं हाथ में चोट पाई और दाहिनी हथेली पर नहीं। इसके अलावा, यह पता चला है कि डॉक्टर द्वारा उल्लिखित चोट संख्या-5 के लिए, सूचक को पी.एम.सी.एच पटना भेजा गया था। इस स्तर पर यह अवलोकन करना भी प्रासंगिक है कि उक्त *फरदबयान* पर डॉक्टर का कोई हस्ताक्षर नहीं है और न ही डॉक्टर का कोई समर्थन है कि घायल सूचक होश में था और बयान देने के लिए मन की स्वस्थ स्थिति में था।

26.1. साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि घायल व्यक्ति तीस दिनों तक पटना में रहा और 30 जुलाई, 2012 को उसने दम तोड़ दिया। अभियोजन पक्ष तीस दिनों की उक्त अवधि के दौरान घायल सूचक को दिए गए चिकित्सा उपचार के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा है। उक्त अवधि के दौरान वह होश में था या बेहोश था, यह ज्ञात नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-10 (अनुसंधान अधिकारी) के अनुसार, वह पी.एम.सी.एच पटना गए थे और फिर जाँच एजेंसी ने घायल मुखबिर की मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बुलाया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि केवल *फरदबयान* के रूप में उपरोक्त मृत्यु घोषणा पर भरोसा करते हुए, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है और आगे पुष्टि की आवश्यकता है।

27. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-5, अभियोजन साक्षी-6, अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8 मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और उक्त गवाहों के बयान से यह कहा जा सकता है कि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी। अधिकांश गवाह घटना स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। इसके अलावा, उपरोक्त गवाहों में से कोई भी विचाराधीन घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना के बाद उपरोक्त सभी गवाह घटना स्थल पर पहुंचे। अभियोजन साक्षी-1 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, वह घटना स्थल पर पहुंचा, घायल ने उसके सामने पूरी घटना सुनाई जिसमें उसने आरोपी का नाम बताया था। इसी तरह अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-5, अभियोजन साक्षी-6, अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8 ने भी कहा है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो घायलों ने पूरी घटना बताई। इस प्रकार, उपरोक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान से यह कहा जा सकता है कि घायल व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक गवाह के सामने अलग-अलग कहानी सुनाई। यह अभियोजन पक्ष के गवाहों का मामला नहीं है कि जब वे सभी घटना स्थल पर पहुंचे, तो घायलों ने उन सभी के सामने कहानी सुनाई। इस प्रकार,

उपरोक्त गवाहों के समक्ष घायलों द्वारा दी गई तथाकथित मृत्यु घोषणा अभियोजन पक्ष की कहानी के संबंध में संदेह पैदा करती है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन साक्षी-3 शिवलाल चौधरी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि अनुसंधान करने वाले अभियोजन साक्षी-10 कुमार संतोष रजक ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने लालबाबू, ज्ञान प्रकाश, ललन साह, सोनमती देवी और छोटे लाल मांझी का बयान दर्ज किया था। अनुसंधान अधिकारी ने आगे स्वीकार किया है कि गवाह लाल बाबू राय ने उसके सामने कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिया और एक रुस्तम अंसारी ने चाकू से वार किया। एक अन्य गवाह ज्ञान प्रकाश ने अपने सामने कहा कि दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था और उक्त गवाह ने आगे कहा कि अन्य व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद नहीं थे। एक अन्य गवाह ललन राय ने यह भी कहा है कि दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था और एक लड़का मौके से भाग गया था और उसके बाद उसे पता चला कि दूसरे लड़के को चाकू मारा गया था। इस प्रकार, पी.डब्लू.-10 (जांच अधिकारी) द्वारा दिए गए बयान से, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह हैं और अनुसंधान अधिकारी ने उक्त गवाहों का बयान दर्ज किया, जो स्वतंत्र गवाह हैं, जिसके बावजूद उपरोक्त गवाह, जिनके नाम जाँच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र में संदर्भित हैं, अभियोजन पक्ष ने उक्त चश्मदीद गवाह की की परीक्षण नहीं की और इस तरह सही तथ्यों को दबा दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त गवाह से पूछताछ न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

28. घायल सूचक की जांच करने वाले डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि 1 से 4 तक की चोट सरल प्रकृति की थी। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान आगे स्वीकार किया है कि चोटों की प्रकृति से पता चलता है कि केवल एक हथियार का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य भी *फरदबयान* में सूचक द्वारा सामने रखी गई कहानी का समर्थन नहीं करते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों ने चाकू से वार किए थे।

29. अभिलेख से आगे यह पता चलता है कि अभियोजन साक्षी-8 (हरीश कुमार), जो मृतक के पिता हैं, के बयान घटना की अगली तारीख यानी 01.07.2012 को दर्ज किया गया था, जबकि अन्य गवाहों का बयान था एक महीने से अधिक समय के बाद दर्ज

किया गया। अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों का बयान केवल अक्टूबर, 2012 में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, यह उपरोक्त गवाहों के सामने घायलों द्वारा दी गई मौखिक मृत्यु घोषणा की कहानी के संबंध में संदेह पैदा करता है।

30. **लखन (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैराग्राफ-10,12 और 21** में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> *"**10.** इस न्यायालय ने बार-बार विभिन्न स्थितियों में दर्ज मृत्यु घोषणाओं की प्रासंगिकता/संभावित मूल्य पर विचार किया है और उन मामलों में भी जहां एक से अधिक मृत्यु घोषणा दर्ज की गई है। कानून यह है कि यदि अदालत संतुष्ट है कि मृत्यु घोषणा सत्य है और मृतक द्वारा स्वेच्छा से की गई है, तो दोषसिद्धि पूरी तरह से उस पर आधारित हो सकती है, बिना किसी और पुष्टि के।यह न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्यु घोषणा पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब मृत्यु की घोषणा संदिग्ध होती है, तो बिना पुष्टि करने वाले साक्ष्य के उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को मृत्यु घोषणा की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि घोषणा शिक्षण, उकसाने या कल्पना का परिणाम नहीं है। घोषणा करने के लिए मृतक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और हमलावरों की पहचान करनी चाहिए। केवल इसलिए कि मृत्यु घोषणा में घटना का विवरण नहीं होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि केवल एक संक्षिप्त बयान है, तो यह इस कारण से अधिक विश्वसनीय है कि बयान की संक्षिप्तता स्वयं इसकी सत्यता की गारंटी है। यदि मृत्यु घोषणा किसी दुर्बलता से ग्रस्त है, तो यह अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। जहां अभियोजन पक्ष का संस्करण मृत्यु घोषणा में दिए गए संस्करण से अलग है, वहां उक्त घोषणा पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। (कुशल राव बनाम बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:106], रशीद बेग बनाम एम. पी. राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 264:1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 426:ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 332], के. रामचंद्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक [(1976) 3 एस. सी. सी. 618:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 473:ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1994], महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू [1980*

एस. सी. सी. 455:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 364], उकाराम बनाम राजस्थान राज्य [(2001) 5 एस. सी. सी. 254:2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 847], बाबूलाल बनाम एम. पी. राज्य [(2003) 12 एस. सी. सी. 490:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 620], मुथु कुट्टी बनाम राज्य [(2005) 9 एस. सी. सी. 113:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1202], राजस्थान राज्य बनाम वाकटेंग [(2007) 14 एस. सी. सी. 550: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 217] और शारदा बनाम राजस्थान राज्य [(2010) 2 एस. सी. सी. 85:(2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 980]।

12. *एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा निम्न रैंक के अधिकारी द्वारा दर्ज की गई घोषणा की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर होगी, क्योंकि सक्षम मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित की मृत्यु घोषणा में नामित व्यक्ति के खिलाफ पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं है, हालांकि, मामले के तथ्यों में कुछ भी विपरीत दिखाने वाली परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। (रवि चंदर बनाम पंजाब राज्य (1998) 9 एस. सी. सी. 303:1998 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1004], हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य [(1999) 6 एस. सी. सी. 545:1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1130], कोली चुनीलाल सावजी बनाम गुजरात राज्य [(1999) 9 एस. सी. सी. 562:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 432] और विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2008) 2 एस. सी. सी. 516:(2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 486]।*

21. *उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मृत्यु घोषणा के मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मृत्यु घोषणा सही और विश्वसनीय है, तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में दर्ज किया गया है जब मृतक घोषणा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था और यह किसी भी शिक्षण/दबाव/संकेत के तहत नहीं किया गया है; यह दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आम तौर*

पर, मृत्यु के समय मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति न हो। यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें घोषणा की गई थी, स्वेच्छा से नहीं और यहां तक कि अन्यथा भी, यह अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अदालत को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और निर्णय लेना होगा कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं।"

31. **सुंदर सिंह (ऊपर)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पैराग्राफ-30 और 31** में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

"30. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मृत्यु घोषणा को दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है। फिर से इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मृत्युदंड की घोषणा पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए, मृत्युदंड की घोषणा को स्वैच्छिकता की सभी परीक्षाओं, मृत्युदंड की घोषणा करने वाले की मानसिक स्थिति और गवाह को किसी अन्य कारक और घोषणा की सच्चाई से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2002) 6 एस. सी. सी. 710 के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा कानून का निपटारा किया गया हैः2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1491] वहाँ, निश्चित रूप से, अदालत ने डॉक्टर के बयान के निहितार्थ पर चर्चा की है। न्यायालय ने आगे षण्मुगम बनाम टी. एन. राज्य [(2002) 10 एस. सी. सी. 4 में इस विषय पर विचार किया हैः2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1501] और पी. वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य [(2003) 6 एस. सी. सी. 443:2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1679] हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि हम डॉक्टरों के साक्ष्य के महत्व को कम नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ हालांकि डॉक्टर द्वारा कोई प्रमाणन नहीं है, फिर भी मृत्यु घोषणा स्वीकार की जा सकती है और हमारी राय में वर्तमान ऐसा मामला है। लक्ष्मण मामले [(2002) 6 एस. सी. सी. 710:2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1491] न्यायालय ने एस. सी. सी. पैरा 3 में कहा थाः(एस. सी. सी. पी. 713)

"3. ... आम तौर पर, इसलिए, अदालत यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, मृत्यु की घोषणा करने के लिए चिकित्सा राय को देखता है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, वहां चिकित्सा राय प्रबल नहीं होगी, और न ही यह कहा जा सकता है कि क्योंकि मस्तिष्क की योग्यता के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है। निश्चित रूप से, मृत्यु घोषणा स्वीकार्य नहीं है।"

यह निर्णय इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिया गया था और इसने पहले के सभी निर्णयों का जायजा लिया है। बाद के मामलों में इस न्यायालय द्वारा इसका पूरे समय पालन किया गया है।

***31.** सभी परिस्थितियों, विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के साक्ष्य की जांच करने के बाद, हमारी स्पष्ट राय है कि विमला देवी और प्रेम सिंह की अंतिम घोषणाएं विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती हैं। बेशक, विमला देवी की मृत्यु घोषणा ठोस सबूत नहीं हो सकती है और यह केवल मौखिक गवाही का पुष्टि करने वाला सबूत हो सकता है क्योंकि वह बच गई थी। हालाँकि, प्रेम सिंह का सबूत ठोस सबूत बन जाता है और हमारी राय में, पूरी तरह से विश्वसनीय है।इसलिए हम मानते हैं कि निचली अदालत और अपीलीय अदालत ने उस अंतिम घोषणा पर भरोसा करने में कोई गलती नहीं की है।"*

32. **तेजराम पाटिल (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पैराग्राफ-15** में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

*"15. जहां तक डी. डी. प्रदर्श 45 की विश्वसनीयता का संबंध है, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के विवाद में योग्यता पाते हैं।हमारा विचार है कि निचली अदालत ने उक्त साक्ष्य को खारिज कर दिया था। निस्संदेह, जैसा कि **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2002) 6 एस. सी. सी. 710** के मामले में उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा था यहां तक कहा था कि घोषणा करने वाले के दिमाग की योग्यता के बारे में डॉक्टर द्वारा प्रमाणन के अभाव में और भले ही डी. डी.*

पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया हो, उस पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक डीडी बनाने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था और बयान ईमानदारी से दर्ज किया गया था और अन्यथा विश्वसनीय था।वर्तमान मामले में, इस तरह की संतुष्टि दर्ज करना मुश्किल है। अदालत के संतुष्ट होने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मृतक घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। मृतक अपने कथित बयान के समय अस्पताल में थी, लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सा स्थिति का पता लगाने या यह प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उसने घोषणा करने वाले की योग्यता के बारे में खुद को संतुष्ट किया है। डीडी पर मृतक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं होता है। मृतक 100 प्रतिशत जल गया था और उसने 29 मार्च, 1999 को सुबह 6.25 बजे दम तोड़ दिया। उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार कि तथ्यों की विशिष्टता में, डी. डी. की प्रामाणिकता को स्वीकार किया जा सकता है, हमारी राय में, सही नहीं है।"

33. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि जिस मामले में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मृत्यु घोषणा सत्य और विश्वसनीय है और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय में दर्ज की गई है जब मृतक घोषणा करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ था और यह किसी भी शिक्षण, दबाव और उकसावे के तहत नहीं किया गया है, यह दोषसिद्धि दर्ज करने का एकमात्र आधार हो सकता है।ऐसी स्थिति में, किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

33.1. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस तरह की संतुष्टि को दर्ज करना मुश्किल है। हमारे सामने वर्तमान मामले में ऐसी कोई सामग्री दर्ज नहीं है जिससे की, ऐसी संतुष्टि की जाए कि मृतक घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अभियोजन साक्षी-10 द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, वह 01.07.2012 को पी.एम.सी.एच पटना गए थे और घायल का बयान लिया था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को घायल की मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए नहीं बुलाया गया था। मृतक तीस दिनों तक जीवित रहा। हालाँकि, जाँच एजेंसी द्वारा घायल की मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष मृतक का कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा है जब उसने पी.एम.सी.एच पटना में इलाज कराया था। इस प्रकार, वर्तमान

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि केवल सूचक द्वारा दी गई तथाकथित मृत्यु घोषणा पर भरोसा करते हुए, *फरदबयान* के रूप में, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है।

34. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को रद्द, एवं निरस्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है।

35. भगवान बाजार थाना कांड संख्या-124/2012 के मामले से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या-765/2012 (सी.आई.एस.पंजीकरण संख्या -4356/2014) में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, छपरों, सारण के द्वारा दिनांक 16.11.2016 का दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और दिनांक 22.11.2016 को सजा का पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और निरस्त कर दिया गया है।

36. आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या- 102/2017 में अपीलार्थी जय राम साह की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकार, जय राम साह के संबंध में अपील समाप्त हो जाती है।

37. सभी अपीलार्थियों को विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

38. अपीलार्थी, अर्थात् विजय राय (आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या-109/2017 में) जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

39. अन्य सभी अपीलार्थी जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत बांड, यदि कोई हो, की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

40. इन सभी अपीलों को स्वीकृत की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।